

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 13, शुक्रवार, शाके 1946-मई 03, 2024 <i>Vaisakha 13, Friday, Saka 1946- May 03, 2024</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(नियम अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2023

जी.एस.आर.02 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (पांचवा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये 01.04.2023 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 14 का संशोधन.- विद्यमान नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“14. मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी).- तीन वित्तीय उन्नयनों के साथ मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) की स्कीम निम्नानुसार होगी:-

(1) यह स्कीम एल-20 से ऊपर के वेतन लेवल वाले पदों और राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा के राज्य सेवा अधिकारियों, जो डायनेमिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (डीएसीपी) के अधीन पदोन्नति के लिए पात्र हों, को छोड़कर, चतुर्थ श्रेणी, लिपिकवर्गीय, अधीनस्थ, राज्य सेवाओं और एकल पदों को धारित करने वालों और इन नियमों के अधीन वेतन आहरित करने वाले समस्त सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध होगी।

(2) (i) मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी) मंजूर किये जाने के लिए, सेवा को, सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवा में नियमित नियुक्ति की तारीख से गिना जायेगा। एमएसीपी के अधीन पहला, दूसरा और तीसरा वित्तीय उन्नयन क्रमशः 9, 18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर अनुज्ञेय होगा।

- (ii) ऐसा कर्मचारी जिसे एक सेवा/संवर्ग से दूसरी सेवा/संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है, एमएसीपी को मंजूर करने के लिए उसकी सेवा सरकारी सेवा में प्रारंभिक नियमित नियुक्ति की तारीख से गिनी जायेगी और वह इन नियमों के अधीन चयन ग्रेड, एसीपी, पदोन्नति या एमएसीपी के रूप में किये गये उपभोग को सम्मिलित करते हुए, कुल तीन वित्तीय उन्नयनों का हकदार होगा।
- (iii) वह सरकारी कर्मचारी, जो पहले से ही चयन ग्रेड सहित एसीपी के अधीन तीन वित्तीय उन्नयनों के फायदे ले चुका है, एमएसीपी मंजूर किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा। वे सरकारी कर्मचारी जो, एक एसीपी/एक पदोन्नति का फायदा ले चुके हैं वे क्रमशः 18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर दूसरी और तीसरी एमएसीपी के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार, वे सरकारी कर्मचारी जो, दो एसीपी/दो पदोन्नति या, यथास्थिति, एक पदोन्नति और एक एसीपी का फायदा ले चुके हैं वे, 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर तीसरी एमएसीपी के लिए पात्र होंगे।

तथापि, वह सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही चयन ग्रेड सहित एसीपी के अधीन वित्तीय उन्नयन के एक या दो या, यथास्थिति, तीन फायदे ले चुका है, इन नियमों के अधीन, पहले या दूसरे या, यथास्थिति, तीसरे एमएसीपी वेतन लेवलों के वेतन लेवल में वेतन के पुनःनियतन के लिए निम्नलिखित रीति से पात्र होगा, अर्थात्:-

1 अप्रैल, 2023 को वेतन के पुनःनियतन की रीति.- ऐसा सरकारी कर्मचारी, जो इन नियमों के अधीन 01.04.2023 को किसी वेतन लेवल में वेतन आहरित कर रहा है, पहली या दूसरी या, यथास्थिति, तीसरी एसीपी का वर्तमान वेतन लेवल यदि इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पहली, दूसरी या तीसरी एमएसीपी वेतन लेवल से निम्नतर है तो उसका वेतन, उस लागू वेतन लेवल के किसी बराबर सेल पर क्रमशः पहली या दूसरी या, यथास्थिति, तीसरी एमएसीपी के अनुज्ञेय वेतन लेवल में पुनः नियत किया जायेगा, यदि लागू वेतन लेवल में ऐसा कोई सेल उपलब्ध न हो तो वेतन को, वेतन मैट्रिक्स में उस लागू वेतन लेवल में के ठीक अगले सेल पर नियत किया जायेगा। यदि वर्तमान वेतन लेवल में का वेतन एमएसीपी के अनुज्ञेय वेतन लेवल के प्रथम सेल के न्यूनतम से कम हो तो उसे, वेतन मैट्रिक्स में के पुनरीक्षित एमएसीपी वेतन लेवल के प्रथम सेल पर नियत किया जायेगा।

दृष्टांत

1	वर्तमान वेतन लेवल: एल-13			वर्तमान वेतन लेवल	एमएसीपी वेतन लेवल
2	एल-13: 58000 में मूल वेतन				

3	वेतन लेवल: एल-14 में अनुज्ञेय एमएसीपी	लेवल	एल-13	एल-14
4	एमएसीपी वेतन लेवल अर्थात् एल-14:59500 में पुनः वेतन	सेल	53100	56100
			54700	57800
			56300	59500
			58000	61300
			59700	63100
			61500	65000
			63300	67000

- (3) (i) पहली एमएसीपी, चतुर्थ श्रेणी/ लिपिकवर्गीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को इन नियमों के संबंध में, जहां कहीं भी अनुज्ञेय हो, उसी सेवा/संवर्ग में के अगले पदोन्नति पद का वेतन लेवल, होगी:

परंतु यदि उसी सेवा/ संवर्ग में कोई भी अगला पदोन्नति पद नहीं हो या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या एकल पदों के संबंध में विहित शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हों तो पहली एमएसीपी, उप-नियम (5) में यथा विनिर्दिष्ट, धारित पद के उसके वेतन लेवल या एसीपी के तत्समान वेतन लेवल, होगी।

- (ii) दूसरी एमएसीपी, चतुर्थ श्रेणी/ लिपिकवर्गीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को इन नियमों के संबंध में, जहां कहीं भी अनुज्ञेय हो, उसी सेवा/संवर्ग में के उस कर्मचारी को उपलब्ध दूसरे पदोन्नति पद का वेतन लेवल, होगी:

परंतु यदि दूसरी पदोन्नति में, उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध पद, वेतन लेवल एल-14 से उच्चतर वेतन लेवल वाला हो या उसी सेवा/संवर्ग में कोई भी दूसरा पदोन्नति पद न हो या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या एकल पदों के संबंध में विहित शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हों तो, दूसरी एमएसीपी, उप-नियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट धारित पद के उसके वेतन लेवल या एसीपी के तत्समान वेतन लेवल, होगी।

- (iii) तीसरी एमएसीपी, चतुर्थ श्रेणी/ लिपिकवर्गीय/ अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों के लिए इन नियमों के संबंध में, जहां कहीं भी अनुज्ञेय है, उसी सेवा/संवर्ग में के उस कर्मचारी के लिए उपलब्ध तीसरे पदोन्नति पद का वेतन लेवल, होगी:

परंतु यदि तीसरी पदोन्नति में, उसी सेवा/संवर्ग में उपलब्ध पद, वेतन लेवल एल-14 से उच्चतर वेतन लेवल वाला हो या उसी सेवा/संवर्ग में कोई भी तीसरा पदोन्नति पद न हो या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या एकल पदों के संबंध में विहित शैक्षणिक अर्हताएं न हों, तो तीसरी एमएसीपी, उप-नियम (5) में यथाविनिर्दिष्ट धारित पद के उसके वेतन लेवल या एसीपी के तत्समान वेतन लेवल, होगी।

- (iv) वे कर्मचारी जो, राज्य सेवा से सीधे रूप से भर्ती किये गये हैं, इन नियमों के संबंध में पहली, दूसरी और तीसरी एमएसीपी के लिए, संबंधित सेवा के 9, 18 और 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात्, उसी सेवा/संवर्ग में के उस कर्मचारी को उपलब्ध पहले, दूसरे या तीसरे पदोन्नति पद के वेतन लेवल हेतु पात्र होंगे:

परंतु यदि पदोन्नति पद का वेतन लेवल, धारित पद के तीन उच्चतर वेतन लेवल से अधिक हो तो एमएसीपी, पदोन्नति पद के वेतन लेवल के स्थान पर विद्यमान वेतन लेवल से अगले, तीसरे वेतन लेवल में मंजूर की जायेगी:

परंतु यह और कि एमएसीपी की मंजूरी वेतन लेवल एल-20 तक ही निर्बंधित रहेगी।

- (v) ऐसा कर्मचारी, जो एक सेवा/संवर्ग से दूसरी सेवा/संवर्ग में पदोन्नत किया गया है वह, आगे और एमएसीपी, यदि देय हो, के लिए सेवा/संवर्ग के संबंधित पदोन्नति पद पर 18 वर्ष या, यथास्थिति, 27 वर्ष की सेवा के पश्चात्, पात्र होगा:

परंतु यदि पदोन्नति पद का वेतन लेवल, धारित पद से तीन उच्चतर वेतन लेवल से अधिक हो तो एमएसीपी, पदोन्नति पद के वेतन लेवल के स्थान पर विद्यमान वेतन लेवल से अगले, तीसरे वेतन लेवल में मंजूर की जायेगी:

- (4) मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन मंजूर किये जाने के लिए, नौ, अठारह या, यथास्थिति, सत्ताईस वर्ष की सेवा की कालावधि, सुसंगत भर्ती नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियमित नियुक्ति की तारीख से गिनी जायेगी। परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी की बढ़ायी गयी ऐसी कालावधि को छोड़कर, ऐसी कालावधि, जिसके दौरान कोई सरकारी कर्मचारी चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित या उसके बिना असाधारण छुट्टी पर रहा हो/रहता है, को भी एमएसीपी मंजूर करने हेतु सेवा की कालावधि की संगणना के लिए गिना जायेगा।
- (5) यदि उसी सेवा/संवर्ग में पहली, दूसरी या, यथास्थिति, तीसरी पदोन्नति के लिए कोई भी पद नहीं हो, या कर्मचारी के पास पदोन्नति के लिए या एकल पदों के संबंध में विहित शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हों तो, एमएसीपी नीचे विनिर्दिष्टानुसार होगी:-

क्र.सं.	वेतन लेवल	एमएसीपी में वेतन लेवल
1	एल-1	एल-2
2	एल-2	एल-3
3	एल-3	एल-4
4	एल-4	एल-5
5	एल-5	एल-8
6	एल-6	एल-8
7	एल-7	एल-8

8	एल-8	एल-10
9	एल-9	एल-10
10	एल-10	(i) एल-12- उन मामलों में जहां अगला पदोन्नति पद राज्य सेवा में है। (ii) एल-11- अन्य मामलों में।
11	एल-11	एल-12
12	एल-12	एल-14
13	एल-13	एल-15
14	एल-14	एल-15
15	एल-15	एल-16
16	एल-16	एल-17
17	एल-17	एल-18
18	एल-18	एल-19
19	एल-19	एल-20

- (6) ऐसे सरकारी कर्मचारी के पास जो, एमएसीपी स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र हैं, एमएसीपी स्कीम के अधीन विद्यमान एसीपी स्कीम के वेतन लेवल या एमएसीपी स्कीम के अधीन वेतन लेवल, जो भी उसके लिए पदोन्नति या अगले वित्तीय उन्नयन तक लाभप्रद हो, के चयन करने का विकल्प होगा। सरकारी कर्मचारी विकल्प का प्रयोग इस नियम के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने के भीतर-भीतर लिखित में करेगा। एक बार किया गया विकल्प का प्रयोग अंतिम होगा।
- (7) सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, एमएसीपी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा।
- (8) वित्तीय उन्नयन के मामले में, पुनरीक्षित वेतन संरचना में एमएसीपी स्कीम के अधीन एक लेवल से दूसरे में वेतन का नियतन, निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात्:-
एक वेतनवृद्धि वर्तमान वेतन लेवल में दी जायेगी जिसमें से कर्मचारी को एमएसीपी मंजूर की गयी है। इस प्रकार प्राप्त अंक को एमएसीपी के वेतन लेवल में के अगले सेल में रखा जायेगा।

दृष्टांत(i)

1	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन लेवल: एल-5		वर्तमान वेतन लेवल	एमएसीपी वेतन लेवल
2	एल-5: 27100 में मूल वेतन	लेवल	एल-5	एल-8
3	वेतन लेवल एल-8 में मंजूर की गयी एमएसीपी		26300	26300
			27100	27100

		सेल	27900	27900
4	वेतन लेवल एल-5 : 27900 में एक वेतनवृद्धि देने के पश्चात् वेतन		28700	28700
			29600	29600
			30500	30500
5	वेतन लेवल अर्थात् एल-8: 28700 एमएसीपी में वेतन		31400	31400

दृष्टांत(ii)

1	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन लेवल: एल-11		वर्तमान वेतन लेवल	एमएसीपी वेतन लेवल
2	एल-11: 50800 में मूल वेतन	लेवल	एल-11	एल-12
3	वेतन लेवल एल-12 में मंजूर की गयी एमएसीपी	सेल	49300	48400
			50800	49900
			52300	51400
4	वेतन लेवल एल-11 : 52300 में एक वेतनवृद्धि देने के पश्चात् वेतन		53900	52900
			55500	54500
5	एमएसीपी वेतन लेवल अर्थात् एल-12: 52900 में वेतन		57200	56100
			58900	57800

(9) यदि पदोन्नति उसी वेतन लेवल में है जैसा कि एसीपी/ एमएसीपी के अधीन मंजूर किया गया है तो, नियमित पदोन्नति के समय वेतन का आगे कोई नियतन नहीं किया जायेगा। तथापि, यदि उच्चतर वेतन लेवल वाले पद पर पदोन्नति की गयी हो तो वेतन मैट्रिक्स में केवल उस वेतन लेवल में का वेतन बराबर सेल पर, और यदि कोई बराबर सेल न हो तो ठीक अगले सेल पर नियत किया जायेगा।

(10) मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) मंजूर करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत ऐसे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची-VI में अंतर्विष्ट हैं।”

3. नियम 15 का संशोधन.- विद्यमान नियम 15 हटाया जायेगा।

4. अनुसूची-VI का संशोधन.- नियम 14 से संलग्न अनुसूची VI के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“अनुसूची-VI
(नियम सं. 14)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (एमएसीपी) मंजूर करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

इन नियमों के नियम 14 के अधीन सरकारी कर्मचारी, तीन वित्तीय उन्नयनों के हकदार हैं। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन (एमएसीपी) मंजूर करने के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत निम्न रूप से होंगे:-

- 1 (i) एमएसीपी मंजूर करने के प्रयोजन के लिए, नियमित सेवा वह होगी जो नियम 5(xiii) में परिभाषित है और नीचे उद्धृत है:-

“5(xiii) “नियमित सेवा” से अभिप्रेत है और इसमें उस पद के लिए सुसंगत भर्ती नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी नियुक्ति पर की गयी सेवा सम्मिलित है। तदर्थ आधार/अर्जेंट अस्थायी आधार पर की गयी सेवा की कालावधि को नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जायेगा। अन्य शब्दों में, सेवा की कालावधि, जो वरिष्ठता के लिए गणनीय है, केवल नियमित सेवा के रूप में ही गिनी जायेगी।
- (ii) एमएसीपी स्कीम के अधीन फायदे प्रदान करने के लिए नियमित सेवा को सीधी भर्ती करने पर नियमित आधार पर, सीधे प्रवेश लेवल में के किसी पद को ग्रहण करने की तारीख से, गिना जायेगा।
- (iii) नियमित नियुक्ति से पूर्व तदर्थ/संविदा आधार पर की गयी सेवा को संगणना में नहीं लिया जायेगा। तथापि, किसी नये विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व किसी दूसरे सरकारी विभाग में के उसी लेवल वाले पद पर, बिना किसी व्यवधान के, पिछली निरंतर नियमित सेवा को भी, केवल एमएसीपी के प्रयोजन के लिए (और नियमित पदोन्नतियों के लिए नहीं) नियमित सेवा अर्हित करने हेतु गिना जायेगा। तथापि, ऐसे मामलों में एमएसीपी के अधीन फायदों पर, नये पद में परिवीक्षा कालावधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने तक विचार नहीं किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि नियमित रूप से भर्ती किये गये पटवारी को उसी लेवल में कनिष्ठ लिपिक के दूसरे पद पर नियुक्त किया गया है तो पटवारी के रूप में उसके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि, को परिवीक्षाकाल को संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के पश्चात्, कनिष्ठ लिपिक के रूप में एमएसीपी मंजूर करने के प्रयोजन के लिए संगणित किया जायेगा।
- (iv) “नियमित सेवा” में असाधारण छुट्टी, जिसके लिए परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी की कालावधि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी द्वारा बढ़ायी गयी है, को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति/ अन्यत्र सेवा, अध्ययन

छुट्टी पर व्यतीत की गयी समस्त कालावधियां और समस्त अन्य प्रकार की छुट्टी सम्मिलित है।

- (2) (i) संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड, जिसके आधार पर संबंधित कर्मचारी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है, के अध्यक्षीन रहते हुए वित्तीय उन्नयन गैर-कृत्यात्मक आधार पर होगा। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित कर्मचारी की पिछले 9 वर्ष की निरंतर सेवा का सेवा रिकॉर्ड देखा जाना है। ऐसे मामलों में जहां पिछले 9 वर्ष का निरंतर सेवा का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

- (क) यदि एमएसीपी मंजूर करने के लिए सरकारी कर्मचारी के 9 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (वा.का.मु.प्र.) उपलब्ध न हों तो उस मामले में कर्मचारियों के पूर्ववर्ती वर्षों के दो वा.का.मु.प्र. तक, विचार में लिये जायेंगे।
- (ख) इसके बाद भी यदि 9 वर्षों का वा.का.मु.प्र. (एपीएआर) उपलब्ध नहीं हो तो एमएसीपी मंजूर करने के लिए अगले वर्षों के शेष वा.का.मु.प्र. पर विचार किया जा सकेगा।
- (ग) कोई भी विभागीय या दाण्डिक कार्यवाही लंबित न हो।
- (घ) विगत वर्षों में वार्षिक वेतनवृद्धियां नियमित रूप से दी गयी हो।
- (ङ) नियंत्रक अधिकारी संतोषजनक सेवा का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

- (ii) उस कर्मचारी के मामले में जिसे उसके असंतोषप्रद रिकॉर्ड के कारण एमएसीपी मंजूरी नहीं की जा सकी थी उसे एमएसीपी, उस तारीख से मंजूर होगी जिसको, वह इस संबंध में विहित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन रहते हुए, संतोषप्रद सेवा रिकॉर्ड के आधार पर उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र बनता हो।

- (iii) नियुक्ति प्राधिकारी, एमएसीपी मंजूर किये जाने से पूर्व, 01.06.2002 को या उसके पश्चात् केवल दो संतान होने के संबंध में कर्मचारी से एक शपथपत्र भी प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारी को, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं, उस तारीख से जिसको उसकी एमएसीपी देय हो जाती है, तीन वर्षों के लिए एमएसीपी/अगली एमएसीपी मंजूर नहीं की जायेगी और इसका कोई भी पारिणामिक प्रभाव एमएसीपी की अगली/पश्चात्पूर्वी मंजूरी पर नहीं पड़ेगा। दो से अधिक संतानों वाले कर्मचारी को निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि संतानों की उस संख्या में 01.06.2002 को बढ़ोतरी नहीं होती:

परंतु जहां किसी कर्मचारी के पूर्ववर्ती प्रसव से केवल एक संतान है किंतु किसी एकल पश्चात्पूर्वी प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है वहां इस प्रकार पैदा हुई संतान को, संतानों की कुल संख्या की गणना के दौरान एक इकाई माना जायेगा:

परंतु यह और कि किसी कर्मचारी की संतानों की कुल संख्या की गणना करने के दौरान पूर्ववर्ती प्रसव से पैदा हुई निःशक्तता से ग्रस्त संतान को नहीं गिना जायेगा:

परंतु यह भी कि कोई सरकारी कर्मचारी जिसने पुनर्विवाह किया है, जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और ऐसे पुनर्विवाह से पहले वह इस खंड के अधीन मॉडिफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मंजूर किये जाने के लिए निरहित नहीं है वह, मॉडिफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन का हकदार होगा, यदि ऐसे पुनर्विवाह द्वारा एकल प्रसव से कोई संतान पैदा होती है।

(3) अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के मामले में, एमएसीपी स्कीम के अधीन फायदों का मंजूर किया जाना सामान्य पदोन्नति को शासित करने वाले नियमों के अध्यधीन होगा। ऐसे मामले राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के उपबंधों और उसके अधीन जारी किये गये अनुदेशों के अधीन विनियमित किये जायेंगे।

(4) एमएसीपी मंजूर किये जाने पर शास्ति का प्रभाव निम्नानुसार होगा:-

शास्ति के प्रकार	एमएसीपी पर प्रभाव
परिनिंदा	परिनिंदा के प्रत्येक आदेश की शास्ति के लिए एक वर्ष के लिए एमएसीपी आस्थगित की जायेगी।
संचयी प्रभाव के बिना वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) रोकना।	संचयी प्रभाव के बिना वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियां) को रोकने के शास्ति के प्रत्येक आदेश के लिए एक वर्ष के लिए एमएसीपी आस्थगित की जायेगी।
संचयी प्रभाव के साथ वार्षिक वेतनवृद्धि (वेतनवृद्धियों) का रोका जाना।	एमएसीपी, उन वर्षों की संख्या के लिए आस्थगित की जायेगी जिसके लिए वार्षिक वेतनवृद्धि (वृद्धियों) के रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गयी है। एमएसीपी मंजूर किये जाने पर प्रत्येक आदेश का पृथक प्रभाव होगा।
पदोन्नति के रोके जाने के लिए शास्ति।	एमएसीपी, ऐसी कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी, जिसके दौरान पदोन्नति से वंचित किया गया हो। यदि पदोन्नति से वंचित करने के आदेश में कालावधि उपदर्शित नहीं की गयी है तो ऐसे मामले में एमएसीपी 7 वर्षों की कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी।
उपेक्षा द्वारा या किसी विधि, नियम या आदेश को भंग करने के कारण, सरकार को कारित किसी धनीय हानि की वेतन में से पूर्णतः या भागतः वसूली।	शास्ति के प्रत्येक आदेश के लिए एमएसीपी एक वर्ष के लिए आस्थगित की जायेगी।

किसी निम्नतर सेवा, ग्रेड या पद पर या निम्नतर टाइम स्केल में या टाइम स्केल में किसी निम्नतर स्तर पर अवनति।	एमएसीपी 7 वर्ष की कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी।
पेंशन के मामले में नियमों के अधीन देय से निम्नतर किसी रकम तक ।	एमएसीपी, उस कालावधि के लिए आस्थगित की जायेगी जिसके लिए पेंशन/ पेंशन का भाग प्रतिधारित किया गया है। यदि 100 प्रतिशत पेंशन को रोक दिया गया है तो एमएसीपी अनुज्ञात नहीं की जायेगी। प्रत्येक आदेश का एमएसीपी के मंजूर करने पर पृथक प्रभाव होगा।

- (5) एमएसीपी केवल वित्तीय फायदों के लिए, सुसंगत लेवल में वैयक्तिक आधार पर नियोजन किये जाने पर ही विचार करती है और इसका परिणाम संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक/कृत्यात्मक पदोन्नति नहीं होगी।
- (6) यदि एमएसीपी के अधीन कोई वित्तीय उन्नयन, आस्थगित किया गया है और 9 वर्ष की संतोषजनक वा.का.मू.प्र. की अनुपलब्धता या वा.का.मू.प्र. में प्रतिकूल टिप्पणियों या राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958 के नियम 17 के अधीन शास्ति के कारण अनुज्ञात नहीं किया गया है तो, पश्चात्पूर्ति वित्तीय उन्नयन के मंजूर किये जाने पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा:
- परंतु यदि एमएसीपी को राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1958, के नियम 16 के अधीन शास्ति के कारण आस्थगित कर दिया गया है तो, पश्चात्पूर्ति वित्तीय उन्नयन पर इसका पारिणामिक प्रभाव पड़ेगा, जो पूर्ववर्ती वित्तीय उन्नयन की मंजूरी में देरी की सीमा तक आस्थगित भी हो जायेगा।
- (7) इस स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन मंजूर करने पर पदनाम, वर्गीकरण या उच्चतर प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- (8) एमएसीपी के अधीन वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूर्ण रूप से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता की स्थिति के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इसी प्रकार, इस आधार पर कि एमएसीपी के अधीन लेवल में कनिष्ठ कर्मचारी को उच्चतर लेवल मिला है, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए कोई भी अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा।
- (9) एमएसीपी स्कीम के अधीन अनुज्ञात लेवल में आहरित वेतन को, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के संबंध में, सेवानिवृत्ति लाभ अवधारित करने के लिए आधार माना जायेगा।
- (10) यदि कोई कर्मचारी उसके विभाग में अधिशेष घोषित हो जाता है और नये विभाग में उसी लेवल या निम्नतर लेवल पर नियुक्त किया जाता है तो, उसके द्वारा पूर्व विभाग में की गयी

नियमित सेवा को एमएसीपी के अधीन वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उसके नये विभाग में नियमित सेवा के प्रति गिना जायेगा।

- (11) यदि नियमित पदोन्नति प्रस्तावित की गयी हो किंतु किसी वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पूर्व कर्मचारी द्वारा उसे नामंजूर कर दिया गया हो तो कोई भी वित्तीय उन्नयन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी का अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है। तथापि, गतिहीनता के कारण यदि वित्तीय उन्नयन अनुज्ञात किया गया हो और कर्मचारी पश्चात्पूर्ति रूप से पदोन्नति नामंजूर कर देता है तो वित्तीय उन्नयन प्रत्याहृत करने का यह आधार नहीं होगा। तथापि, वह आगे और वित्तीय उन्नयन पर विचार किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह फिर से पदोन्नति के विचार किये जाने के लिए सहमत न हो जाये और नामंजूरी के कारण आस्थगन की कालावधि की सीमा तक अगले वित्तीय उन्नयन को भी आस्थगित किया जायेगा।

- (12) दृष्टांत:-

- (i) यदि लेवल-5 में का कोई सरकारी कर्मचारी (कनिष्ठ सहायक/लिपिक ग्रेड-II) 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर, लेवल-8 में पहली नियमित पदोन्नति प्राप्त करता है और फिर बिना किसी पदोन्नति के 10 वर्ष की और सेवा पूर्ण करता है तो वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) पूर्ण करने के पश्चात्, एमएसीपी के अधीन दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा।
- (ii) यदि तत्पश्चात् उसके बाद उसे कोई पदोन्नति नहीं मिलती है तो, उसे अगले और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर अर्थात् 27 वर्ष (8+10+9 वर्ष) के पश्चात्, तीसरा वित्तीय उन्नयन मिलेगा।

- (13) एमएसीपी की मंजूर की जाने के पश्चात् अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख अपरिवर्तित रहेगी।

- (14) 'लेवल' शब्द में 'ग्रेड वेतन और वेतनमान', यदि कोई हो, भी सम्मिलित होंगे।

2. आगे और स्पष्टीकरण, यदि कोई अपेक्षित हो, उसे वित्त विभाग के नियम अनुभाग को संबोधित किया जाये।

[सं.एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017पार्ट]

राज्यपाल के आदेश से,

रोहित गुप्ता,
शासन सचिव,
वित्त (बजट)।

**FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 06, 2023

G.S.R.02 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2017, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) (Fifth Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.04.2023.

2. Amendment of Rule 14.- the existing rule 14 shall be substituted by the following, namely. -

"14. Scheme of Modified Assured Career Progression (MACP). - The scheme of Modified Assured Career Progression (MACP) with three financial upgradations shall be as under: -

- (1) The scheme will be available to all Government servants in Class IV, Ministerial, Subordinate, State Services and those holding isolated posts and drawing pay under these rules excluding posts carrying Pay Level above L-20 and State Service officers of Rajasthan Medical & Health Service and Rajasthan Medical Education Service who are eligible for promotion under Dynamic Assured Career Progression Scheme (DACP).
- (2) (i) For grant of Modified Assured Career Progression Scheme (MACP), the service shall be counted from the date of the regular appointment in Government service as per provisions of service rules. The First, Second and Third financial upgradation under MACP shall be admissible on completion of 9, 18 and 27 years of regular service respectively.
- (ii) An employee who is promoted from one service/cadre to another service/cadre, his/her service for grant of MACP shall be counted from the date of initial regular appointment in Government service and he will be entitled to total three financial upgradation including availed as selection grade, ACP, promotion or MACP under these rules.
- (iii) Government servant who have already availed benefits of three financial upgradation under ACP including Selection Grade will not be eligible for the grant of MACP. Those Government servants who have availed benefit of one ACP / one promotion will be eligible for second and third MACP on completion of 18 and 27 years of regular service, respectively. Similarly, those Government servants who have availed benefit of two ACP / two promotions / one promotion and one ACP, as the case may be, will be eligible for third MACP on completion of 27 years of regular service.

However, the Government servant who have already availed one or two or three benefits of financial upgradation under ACP including Selection Grade, as the

case may be, will be eligible for re-fixation of pay under these rules in the Pay Level of first or second or third MACP Pay Levels, as the case may be, by the following manner, namely: -

Method of Re-fixation of pay as on 1st April, 2023. — A Government servant who is drawing pay in a Pay Level as on 01.04.2023 under these rules, if the present Pay Level of first or second or third ACP, as the case may be, is lower than Pay Level the first, second or third MACP admissible under these rules, his/her pay shall be re-fixed in the admissible Pay Level of first or second or third MACP respectively, as the case may be, at an equal Cell of that applicable Pay Level, if no such Cell is available in the applicable Pay Level, the pay shall be fixed at the immediate next Cell in that applicable Pay Level in the Pay Matrix. In case the pay in the present Pay Level is less than the minimum of the first Cell of the admissible Pay Level of MACP, he shall be fixed at first Cell of revised MACP Pay Level in the Pay Matrix.

Illustration

1	Present Pay Level: L-13			
2	Basic Pay in L-13: 58000		Present Pay Level	MACP Pay Level
3	MACP admissible in Pay Level: L-14			
4	Re-fixed Pay in the MACP Pay Level i.e. L-14: 59500	Levels	L-13	L-14
		Cells	53100	56100
			54700	57800
			56300	59500
			58000	61300
			59700	63100
			61500	65000
			63300	67000

- (3) (i) The first MACP, wherever admissible in terms of these rules to employees of Class–IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the next promotion post in the same service / cadre;

Provided that in case there is no next promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the first MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post or ACP held as specified in sub-rule (5).

- (ii) The second MACP, wherever admissible, in terms of these rules to employees of Class–IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre;

Provided that in case the second promotion, post available in the same service/ cadre carries a Pay Level higher than the Pay Level L-14 or there is no second promotion post in the same service/ cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the second

MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post held or the ACP, as specified in sub-rule (5).

- (iii) The third MACP, wherever admissible, in terms of these rules to employees of Class—IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the third promotion post available to that employee in the same service / cadre;

Provided that in case the third promotion, post available in the same service/ cadre carries a Pay Level higher than the Pay Level L-14 or there is no third promotion post in the same service/ cadre or the employees does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the third MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post held or the ACP, as specified in sub-rule (5).

- (iv) The first, second and third MACP in terms of these rules to employees who is directly recruited in State Service, shall be eligible the Pay Level of the first, second or third promotion post available to that employee in the same service/cadre after completion of 9, 18 and 27 years of service respectively.

Provided that the Pay Level of the promotion post is more than three Pay Levels higher to the post held, then the MACP shall be granted in the next third Pay Level from existing Pay Level instead of Pay Level of promotion post.

Provided further that the grant of MACP shall be restricted to the Pay level L-20.

- (v) The employee who is promoted from one service/cadre to another service/cadre shall be eligible for further MACP, if due, after 18 years or 27 years of service, as the case may be, of the respective promotion post of the service/cadre.

Provided that the Pay Level of the promotion post is more than three Pay Levels higher to the post held, then the MACP shall be granted in the next third Pay Level from existing Pay Level instead of Pay Level of promotion post.

- (4) For grant of financial upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme, the period of service of Nine, Eighteen or Twenty-Seven years, as the case may be, shall be counted from the date of regular appointment in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules. The period during which a Government servant remained/ remains on extra ordinary leave with or without medical certificate shall also be counted for reckoning the period of service for grant of MACP except the extended period of probation trainee.
- (5) In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/ cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the MACP shall be as specified below: -

S. No.	Pay Level	Pay Level in MACP
1	L-1	L-2
2	L-2	L-3
3	L-3	L-4
4	L-4	L-5
5	L-5	L-8
6	L-6	L-8
7	L-7	L-8
8	L-8	L-10
9	L-9	L-10
10	L-10	(i) L-12 - in those cases where next promotion post is in State Service. (ii) L-11 - in other cases.
11	L-11	L-12
12	L-12	L-14
13	L-13	L-15
14	L-14	L-15
15	L-15	L-16
16	L-16	L-17
17	L-17	L-18
18	L-18	L-19
19	L-19	L-20

- (6) A Government servant who is eligible for financial upgradation under MACP Scheme have an option to elect the Pay Level of existing ACP Scheme or Pay Level under MACP Scheme, whichever is beneficial to him/her till the promotion or next financial upgradation. The Government Servant shall exercise the option in writing within three months of the date of publication of this rule. The option once exercised shall be final.
- (7) The authority competent to make appointment on the post held by the Government servant shall be competent to grant MACP.
- (8) The fixation of pay in case of financial upgradation under the MACP scheme from one Level to another in the revised pay structure shall be made in the following manner, namely: -

One increment shall be given in the present Pay Level from which the employee is granted MACP. The figure so arrived shall be placed at the next Cell in Pay Level of the MACP.

Illustration (i)

1	Pay Level in the revised pay structure : L- 5			
2	Basic Pay in L-5: 27100	Levels	Present Pay Level	MACP Pay Level
3	Granted MACP in Pay Level L-8			
4	Pay after giving one increment in Pay		L-5	L-8

	Level L-5: 27900		26300	26300
5	Pay in the MACP Pay Level i.e L-8 : 28700		27100	27100
			27900	27900
		Cells	28700	28700
			29600	29600
			30500	30500
			31400	31400

Illustration (ii)

1	Pay Level in the revised pay structure : L-11		Present Pay Level	MACP Pay Level
2	Basic Pay in L-11 : 50800			
3	Granted MACP in Pay Level L-12			
4	Pay after giving one increment in Pay Level L-11: 52300	Levels	L-11	L-12
5	Pay in the MACP Pay Level i.e. L-12: 52900		49300	48400
			50800	49900
			52300	51400
		Cells	53900	52900
			55500	54500
			57200	56100
			58900	57800

(9) There shall be no further fixation of pay at the time of regular promotion, if promotion is in the same Pay Level as granted under ACP/MACP. However, if promotion is on the post carrying higher Pay Level than only the pay in that Pay Level in the Pay Matrix shall be fixed at the equal Cell and if there is no equal Cell than at the immediate next Cell.

(10) The detailed guidelines for grant of Modified Assured Career Progressions (MACP) shall be as contained in Schedule-VI appended to these rules."

3. Amendment of Rule 15.- the existing rule 15 shall be deleted.

4. Amendment of Schedule-VI. - the existing Schedule VI appended to rule 14 shall be substituted, by the following, namely: -

Schedule VI
(Rule No. 14)

Guidelines for grant of Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) to State Government Employees

Under Rule 14 of these rules, the Government servants are eligible for three financial upgradations. The detailed guidelines for grant of Modified Assured Career Progression (MACP) shall be as under: -

- (1) (i) Regular service for the purpose of grant of MACP shall be as defined in Rule 5(xiii) reproduced below; -

"5(xiii) "Regular Service" means and includes service rendered by a Government servant on his appointment after regular selection in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment rules for that post. The period of service rendered on ad-hoc basis / urgent temporary basis shall not be counted as the regular service. In other words, the period of service which is countable for seniority shall only be counted as regular service."

- (ii) Regular service for grant of benefits under the MACP Scheme shall be counted from the date of joining of a post in direct entry Level on regular basis on direct recruitment.

- (iii) Service rendered on ad-hoc/ contract basis before regular appointment shall not be taken into reckoning. However, past continuous regular service in another Government Department in a post carrying same Level prior to regular appointment in a new Department, without a break, shall also be counted towards qualifying regular service for the purpose of MACP only (and not for the regular promotions). However, benefits under the MACP in such cases shall not be considered till the satisfactory completion of the probation period in the new post. To illustrate, in case of Patwari regularly recruited is appointed to another post of LDC in the same Level, the period of service rendered by him as Patwari shall be reckoned for the purpose of grant of MACP as LDC after satisfactory completion of probation period.

- (iv) 'Regular Service' shall include all periods spent on deputation / foreign service, study leave and all other kind of leave except Extraordinary leave for which probation trainee period has been extended by the sanction of the competent authority.

- (2) (i) The financial upgradation would be on non-functional basis subject to satisfactory service record on the basis of which the concerned employee is eligible for promotion on higher post. For this purpose, the service record of the concerned employee of last continuous 9 years' service is to be seen. In cases where the service record of last continuous 9 years is not available, the following procedure shall be adopted: -

- (a) In case 9 years Annual Performance Appraisal Report (APAR) of Government Servant are not available for grant of MACP in that case up to 2 APARs of previous years of employees shall be taken into account.

- (b) Even after that 9 years APAR is not available than remaining APAR may be considered of the next years for grant of MACP.

- (c) Any departmental or criminal proceeding may not be pending.

- (d) In the past years annual increments were regularly granted.

- (e) The Controlling Officer shall issue a certificate of satisfactory service.

- (ii) In case of employee who could not be granted MACP due to his unsatisfactory record, he will be granted MACP from the date he becomes eligible for promotion to the

higher post on the basis of satisfactory service record subject to the fulfillment of other conditions prescribed in this regard.

- (iii) The appointing authority shall also obtain an affidavit from the employee with reference to having only two children on or after 01.06.2002 prior to granting MACP. An employee who has more than two children on or after 01.06.2002 shall not be granted MACP/next MACP for three years from the date on which his/her MACP becomes due and it would have no consequential effect on the next/subsequent grant of MACP. The employee having more than two children shall not be deemed to have been disqualified, so long as the number of children he/she has on 01.06.2002 does not increase;

Provided that Where an employee has only one child from earlier delivery but more than one child is born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children;

Provided further that while counting the total number of children of an employee, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted;

Provided further also that any Government Servant who is remarried, which is not against any law and before such remarriage he/she is not disqualified for grant of Modified Assured Career Progression under this clause, he/she shall be entitled to Modified Assured Career Progression, if any child is born out of single delivery from such remarriage.

- (3) In the matter of disciplinary proceedings, grant of benefit under the MACPS shall be subject to rules governing normal promotion. Such cases shall, therefore, be regulated under the provisions of the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 and instructions issued thereunder.
- (4) The effect of penalty on grant of MACP shall be given as under: -

Kind of Penalty	Effect on MACP
Censure	MACP will be deferred for one year for penalty of each order of censure.
Withholding of annual increment(s) without cumulative effect	MACP will be deferred for one year for each order of penalty of withholding of annual increment(s) without cumulative effective.
Withholding of annual increment(s) with cumulative effect	MACP will be deferred for number of years for which penalty of withholding of number of annual increment(s) has been imposed. Each order will have separate effect on grant of MACP.
Penalty of withholding of promotion	MACP will be deferred for the period for which promotion has been deprived. If in the order of deprive of promotion the

	period has not been indicated in that case MACP will be deferred for a period of 7 years.
Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the government by negligence or breach of any law, rule or order	MACP will be deferred for one year for each order of penalty.
Reduction to a lower service, grade or post, or to a lower time scale or to a lower stage in the time scale	MACP will be deferred for a period of 7 years.
In the case of pension to an amount lower than that due under the rules	MACP will be deferred for the period for which pension / part of pension has been retained. MACP will not be allowed in case 100% pension has been withheld. Each order will have separate effect on grant of MACP.

The MACPs contemplates merely placement on personal basis in the relevant Level for financial benefits only and shall not amount to actual / functional promotion of the employees concerned.

- (6) If a financial upgradation under the MACPs is deferred and not allowed due to non-availability of 9 years' satisfactory APAR or adverse remarks in the APAR or due to penalty under Rule 17 of Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958, would not have consequential effect on grant of subsequent financial upgradation;

Provided that MACPs is deferred due to penalty under Rule 16 of the Rajasthan Civil Services (CCA) Rules, 1958, would have consequential effect on the subsequent financial upgradation which would also get deferred to the extent of delay in grant of previous financial upgradation.

- (7) On grant of financial upgradation under the Scheme, there shall be no change in the designation, classification or higher status.
- (8) Financial upgradation under the MACPs shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such, there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the Level has got higher Level under the MACPs.
- (9) Pay drawn in the Level allowed under the MACPs scheme shall be taken as the basis for determining the terminal benefits in respect of the retiring employee.
- (10) In case an employee is declared surplus in his / her department and appointed in the same Level or lower Level in the new department, the regular service rendered by him / her in the previous department shall be counted towards the regular service in his / her new department for the purpose of giving financial upgradation under the MACPs.

- (11) If a regular promotion has been offered but was refused by the employee before becoming entitled to a financial upgradation, no financial upgradation shall be allowed as such an employee has not been stagnated due to lack of opportunities. If, however, financial upgradation has been allowed due to stagnation and the employee subsequently refuses the promotion, it shall not be a ground to withdraw the financial upgradation. He shall, however, not be eligible to be considered for further financial upgradation till he agrees to be considered for promotion again and the next financial upgradation shall also be deferred to the extent of period of deferment due to the refusal.
- (12) Illustration: -
- (i) If a Government servant (Junior Assistant / Clerk Gr.-II) in Level-5 gets his first regular promotion in Level-8 on completion of 8 years of service and then completes service of further 10 years without any promotion then he would be eligible for 2nd financial upgradation under the MACP after completion of 18 years (8+10 years).
- (ii) In case he does not get any promotion thereafter, then he would get 3rd financial upgradation on completion of further 9 years of service i.e. after 27 years (8+10+9 years).
- (13) The next annual increment date shall remain unchanged after grant of MACP.
- (14) The word 'Level' shall also include 'Grade Pay and Scale of Pay', if any.
2. Further clarifications, required if any, be addressed to the Rules Division of the Finance Department.

[No. F. 15(1)FD/Rules/2017 Pt.]
By order of the Governor,

Rohit Gupta,
Secretary to the Government,
Finance (Budget).

Government Central Press, Jaipur.